

प्रधानमंत्री कार्यालय

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 'वैश्विक निवेशक बैठक 2019' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 07 NOV 2019 3:32PM by PIB Delhi

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रहलाद पटेल जी, अनुराग ठाकुर जी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी, UAE के भारत में एंबेसेडर डॉक्टर अहमद अल्बाना, उद्योग जगत के दिग्गज साथी, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्रिय साथियों धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट !!!

ये कल्पना नहीं, सच्चाई है, अभूतपूर्व है, अद्भुत है, बधाई हो आपको। ये हिमाचल प्रदेश का एक स्टेटमेंट है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हम भी अब कमर कस चुके हैं।

आज हिमाचल कह रहा है- Yes, We Have Arrived !!! इसलिए सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, जयराम जी और उनकी टीम को मां जवाला जी के सानिध्य में इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों, आज हम सभी एक ऐसे स्थान पर एकत्र हुए हैं जहां कण-कण में शक्ति का वास है,

जहां आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। देवियों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने इस स्थान को दिव्यता भी दी है और प्राकृतिक संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया है। इस वातावरण में आप सभी Wealth Creators का स्वागत करते हुए मुझे आनंद हो रहा है।

भाइयों और बहनों, पहले इस प्रकार के Investors Summits देश के कुछ ही राज्यों में हुआ करते थे। यहां अनेक ऐसे साथी मौजूद हैं जिन्होंने पहले की स्थितियां देखी हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और इसकी एक गवाह यहां हिमाचल में हो रही ये समिट भी है। अब राज्यों में बिजनेस को आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई होड़ शुरू हुई है।

साथियों, कुछ दशक पहले हमारे देश में ये हालत थी कि कौन सा राज्य ज्यादा चैरिटी करेगा, कौन ज्यादा Incentive देगा, कोई टैक्स माफ करेगा, कोई बिजली माफ करेगा, कोई जमीन सस्ती बेचेगा यही स्पर्धा चलती रहती थी। अनुभव यही कहता है कि इस तरह की स्पर्धा ने वो परिणाम नहीं दिए, जैसे अपेक्षित थे। तब निवेशक भी इस इंतजार में रहते थे कि अब कौन सा राज्य ज्यादा से ज्यादा रियायत देगा, Incentive देगा। इस कारण Investors भी किसी राज्य में निवेश का निर्णय टालते रहते थे। उन्हें भी लगता था कि भाई, 5 परसेंट छूट क्यों लें, हो सकता है आगे 10 परसेंट, या 15 परसेंट की छूट मिल जाए।

लेकिन साथियों, मुझे संतोष है कि पिछले कुछ वर्षों में, इस स्थिति में भी आमूल-चूल परिवर्तन आया है। अब राज्य सरकारें समझने लगी हैं कि रियायतों की स्पर्धा न राज्य का भला करती है और न ही उद्योगों का।

साथियों, निवेशक के लिए ये आवश्यक है कि उसे उपयुक्त इको-सिस्टम मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। इन दिनों सरकारें इस इको-सिस्टम को बनाने की स्पर्धा में आगे आ रही हैं, व्यवस्था सरल कर रही हैं, कानूनों में बदलाव कर रही हैं, गैर-जरूरी नियमों को समाप्त कर रही हैं। राज्यों में ये कंपटीशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कंपीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे,

दूसरे उद्योगों से मुकाबला करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ राज्यों को होगा, राज्य के लोगों को होगा, देशवासियों को होगा और हिन्दुस्तान तेज गति से आगे बढ़ेगा।

साथियों, उद्योग जगत भी तो पारदर्शी और साफ-सुथरी व्यवस्था को पसंद करता है। बेवजह के नियम कायदे, सरकार का बहुत ज्यादा दखल कहीं न कहीं उद्योगों के बढ़ने की रफ्तार को रोकता है। मुझे खुशी है कि इसी सोच के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार भी कई नए incentive ले रही है, महत्वपूर्ण निर्णय कर रही है, सही दिशा में सरकार भी काम कर रही है। यहां सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था का निर्माण हो, Land Allotment को ट्रांसपेरेंट किया जाना हो या फिर सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्री पॉलिसी का गठन, इन कदमों ने यहां के Friendly Environment को Business Friendly भी बना दिया है।

साथियों, यहां इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गज जुटे हुए हैं। आप सभी, उद्योग जगत के अन्य साथी इसे भी भली-भांति समझते हैं कि जब कंपनी की अलग-अलग यूनिट्स अच्छा रिजल्ट देती हैं तो कंपनी का भी रिजल्ट अपने-आप सुधर जाता है। इसलिए राज्यों में जब कुछ बेहतर होता है,

तो इसका सीधा प्रभाव देश के नतीजों पर पड़ता है। हिमाचल जैसे अनेक राज्यों में हो रहे बदलावों की वजह से ही आज भारत की पहचान, पहले से कहीं बेहतर Business Friendly Destination के तौर पर बनी है।

साथियों, आज भारत में विकास की गाड़ी नई सोच, नई अप्रोच के साथ 4 Wheels पर चल रही है। एक Wheel सोसायटी का, जो Aspiring है। एक Wheel सरकार का, जो नए भारत के लिए Encouraging है, एक Wheel Industry का, जो Daring है और एक Wheel ज्ञान का, जो Sharing है। इस प्रकार से इन 4 Wheel पर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

आज सरकार जो भी फैसले ले रही है, वो भारत के हित के अनुसार, भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है। आज सरकार गरीब के घर, स्वास्थ्य, स्किलपर फोकस कर रही है, तो साथ-साथ Investment और Self-Employment पर भी बल दे रही है।

आज जितना महत्व Service Delivery पर है, उतना ही फोकस Business का माहौल सुधारने पर भी है। इसका भी नतीजा आपके सामने है। 2014 से 2019 के बीच भारत ने Ease Of Doing Business Ranking में 79 Rank का सुधार किया है। इस बार भी हम दुनिया के टॉप 10 Performers में से एक हैं। हर साल हम एक नए पैरामीटर में तेजी से सुधार कर रहे हैं। पिछले साल हमने 10 में से 6 Indicators उसमें सुधार करने में सफलता पाई है। इस बार Insolvency के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी जंप लगाई है। इस कैटेगरी में हमने 50 से ज्यादा रैंक का सुधार किया है।

साथियों, ये रैंकिंग सुधारने का मतलब सिर्फ आंकड़ों का फेरबदल नहीं है। ये रैंकिंग सुधारने का मतलब है कि हमारी सरकार जमीन पर जाकर, जमीन की जरूरतों को समझते हुए फैसले ले रही है, नीतियां बना रही है। यहां जो लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि कैसे पहले एक-एक परमीशन के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता था।

साथियों, ये सिर्फ रैंकिंग में सुधार नहीं, बल्कि भारत में बिजनेस करने के तरीके में एक Revolution है और इस Revolution में साल दर साल हम नए आयाम जोड़ रहे हैं, नए सुधार कर रहे हैं। आज के ग्लोबल सीनेरियो में, भारत अगर आज मजबूती से खड़ा है, तो इसलिए, क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स को कमजोर नहीं पड़ने दिया है।

हमने Macro-economic में अपनी प्रतिबद्धता निरंतर बनाए रखी है और Fiscal Discipline का कड़ाई से पालन किया है। आज जब Global Economic Activity³ प्रतिशत तक नीचे आ गई है, भारत 5 प्रतिशत से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये उम्मीद जता रही हैं कि भारत आने वाले महीनों में और तेजी से आगे बढ़ेगा।

साथियों, हमारी नीयत नेक है और संवेदनशील भी। हमारे फैसलों में मजबूती है और इरादों में भी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि GST कभी भारत में लागू होगा। हमने ये करके दिखाया। दीवालिया होने की स्थिति में देश की कंपनियों के पास कोई स्पष्ट Exit Route नहीं था।

आज Insolvency and Bankruptcy Code - IBC न सिर्फ एक सच्चाई है बल्कि लाखों करोड़ की फंसी हुई राशि की वापसी का कारण बन रहा है। Banking Reform भी बरसों से अटका हुआ था। इस दिशा में भी तेजी के साथ, बुलंद हौसले के साथ हमारी ही सरकार आगे बढ़ी। कल ही हमने देश के मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए लेकिन कल शाम को हमने कैबिनेट में मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से साढ़े चार लाख से ज्यादा परिवारों के, अपने घर के सपनों को, उनके बरसों से अधूरे सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और इसी इरादे के साथ अब हमने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है।

हमारी सरकार सरकारी प्रक्रियाओं की De-Bottle-necking पर बल दे रही है, Inter Department Co-Ordination को बढ़ा रही है, Time Limit में फैसले ले रही है।

हमारी कोशिश Tax Regime को Competitive और Transparent बनाने की है। इस कड़ी में ही Corporate Tax से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज भारत दुनिया की सबसे कम Corporate Tax व्यवस्थाओं में से एक है। इस साल एक अक्टूबर के बाद जो भी नई घरेलू कंपनियां खुली हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर सिर्फ 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

साथियों, पिछले महीने ही E-Assessment Scheme लागू की जा चुकी है। यानी टैक्स सिस्टम में अब Human Interface को कम से कम किया जा रहा है। इससे अधिक Transparency आएगी और Tax से जुड़े मामलों का भी तेजी से निपटारा होगा।

साथियों, 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है। ये लक्ष्य देश के हर राज्य के सहयोग से ही प्राप्त होगा। हमारे यहां हर राज्य में अनेक संभावनाएं हैं, राज्य के हर जिले में अनेक संभावनाएं हैं, बहुत Potential है। इस Potential का जितना ज्यादा लाभ सरकारें, हमारा उद्योग जगत, हमारे लघु उद्योग, हमारा सर्विस सेक्टर उठाएगा, उतनी ही तेजी से हम आगे बढ़ेंगे।

भाइयों और बहनों, Potential को जब Policy का साथ मिलता है, तो Performance बढ़ जाती है। ये Performance ही Progress लाती है। यानी जिले की, राज्य की, देश की Progress inter-connected है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण में इंटरनेशनल रैंकिंग भी है, Potential भी है। और हिमाचल के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लिए आज हमने जो tourism sector में ranking किया है उसका सीधा लाभ आज हिमाचल को मिलने की संभावना है।

साथियों, साल 2013 में भारत, World Economic Forum के Travel and Tourism Competitiveness Index में 65वें नंबर पर था। आज हम 34वें नंबर पर हैं। आखिर ये बदलाव कैसे आया? पाँच साल पहले भारत में सालाना करीब 70-75 लाख विदेशी टूरिस्ट आते थे। पिछले साल ये आंकड़ा 1 करोड़ विदेशी टूरिस्ट को पार कर चुका है। आखिर ये वृद्धि कैसे हुई?

साथियों, 2014 में भारत के लोगों को टूरिज्म सेक्टर से विदेशी मुद्रा में 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। वहीं पिछले साल ये विदेशी मुद्रा बढ़कर करीब-करीब 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। ये परिवर्तन भी कैसे आया?

साथियों, हमने टूरिज्म सेक्टर के Potential को समझा, Travel And Tourism सेक्टर में Policy Intervention किए, दर्जनों नए देशों को e-Visa की सुविधा दी और इसी का नतीजा था कि Performance बदल गई, रैंकिंग बदल गई।

साथियों, आज भारत में टूरिज्म को एक Package की तरह Promote किया जा रहा है। Nature हो, Adventure हो, Spiritual हो, Medical हो, Eco हो, हर प्रकार के Tourism पर बल दिया जा रहा है। और हिमाचल इस मामले में संभावनाओं से भरपूर है। इतना अच्छा आयोजन आज यहां हो रहा है। इसलिए Conference Tourism की संभावनाएं तो हमें साक्षात् दिख रही हैं। हम इस Potential को समझ लेंगे तो Progress बहुत दूर नहीं रह जाएगी।

साथियों, अभी यहां जो कॉफी टेबल बुक रिलीज हुई है या जो फिल्म दिखाई गई है, उसमें हिमाचल के Potential को विस्तार दिया गया है। मुझे याद है जब मैं सोलन जाता था,

तो कई बोर्ड लगे देखता था कि- मशरूम सिटी में आपका स्वागत है। इसी तरह लाहौल-स्पीति के आलू, कुल्तू की शॉल, कांगड़ा की पेंटिंग भी तो मशहूर है। लेकिन अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं, उन्हें ये कम ही पता होता है। प्रत्येक जिलों को पहचान देने वाली इन चीजों को कैसे प्रमोट किया जाए, इस बारे में भी नए तरीके सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि हिमाचल का Potential अब भी Untapped है।

अब सोचिए, हिमाचल में IIT है, ट्रिपल IT है, NIT है, CIPET है, IIFT पर काम हो रहा है। ऐसे में यहां टेक्नोलॉजी के विस्तार का Potential है। यहां के सेब, नाशपाति, प्लम जैसे फलों से लेकर टमाटर, गुच्छी, मशरूम, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों तक की डिमांड है। इसलिए यहां के फूड, फूड प्रोसेसिंग, फार्मिंग और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त Potential है।

साथियों, यहां हमेशा से ऑर्गेनिक खेती होती रही है। देश की ऐसी शायद ही कोई Pharma कंपनी हो जो हिमाचल में दवाइयों की Manufacturing ना करती हो। इस सेक्टर के विस्तार के लिए भी यहां खूब संभावनाएं हैं।

हां, मैं मानता हूं कि इन अपार संभावनाओं के बीच, पहले हिमाचल में एक Gap महसूस होता था। ये Gap था Quality Infrastructure और सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण का। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस Gap को भरने की पूरी कोशिश की है। जब से यहां जयराम जी की टीम को अवसर मिला है, तबसे ये प्रक्रिया और तेज़ हुई है।

आज हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोपावर के साथ-साथ Renewable Energy के दूसरे स्रोत हों या फिर रोड, रेल या

एयर कनेक्टिविटी हर स्तर पर तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे बताया गया है कि उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने हेली-टैक्सी सेवा आरंभ की है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, चंडीगढ़ इस सुविधा से जुड़ गए हैं।

इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए के निवेश से नेशनल हाईवेज का भी विस्तार किया जा रहा है। रोहतांग सुरंग का काम पूरा होने का लाभ तो लाहौल-स्पिति और लद्दाख तक को मिलेगा। वहीं 'नंगल डैम-तलवाड़ा' रेल लाइन, 'चंडीगढ़-बददी' रेल लाइन, 'ऊना-हमीरपुर' रेल लाइन और 'भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी' रेल लाइन इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया आयाम देंगी। अगले कुछ वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लाभ हिमाचल को भी मिलने वाला है।

साथियों, आज सही मायने में हिमाचल, भारत की गोथ स्टोरी को नई रोशनी देने के लिए तैयार है और मेरे इस विश्वास के पीछे हिमाचल की मेरी अपनी समझ है। हिमाचल Business के लिए हर ज़रूरी शर्त को पूरा करता है। बिजनेस के लिए Peace चाहिए, वो हमेशा हिमाचल की ताकत रही है। Diversity को स्वीकार करने वाली सोसायटी चाहिए, वो हिमाचल में हमेशा से मौजूद रही है। यहां Geographical और Linguistic Diversity भी बहुत अधिक है। एक दूसरे की बोली कई बार समझ तक नहीं आती, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव अद्भुत है।

इसके साथ-साथ हिमाचल देश के उन राज्यों में है, जहां Literacy Rate High है। हिमाचल के कोने-कोने में आपको व्यापार, व्यवसाय में लगे लोग दिख जाएंगे। वो सरकार का इंतजार नहीं करते। जो भी संसाधन उनके पास होते हैं वो उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। यहां के लोगों के भीतर एक स्वाभाविक उद्यम भावना है, जिसका लाभ निवेशकों को होता है।

इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, देश के रक्षा क्षेत्र की भी बहुत बड़ी ताकत है। यहां का कोई परिवार ऐसा नहीं है जो सैन्य बल न जुड़ा हो। और दूसरी बात है आप हिमाचल के किसी गांव में जा कर बैठोगे क्योंकि मेरा यहां काफी अनुभव रहा है और गांव वालों से बातें करोगे तो एक प्रकार से आपको वहां लघु भारत मिलेगा। हमारे रिटायर्ड फौजियों के तौर पर हिमाचल प्रदेश के पास उनका अनुभव, बहुत बड़ा Skill-Set है। अनेक सेक्टर्स के लिए और विशेषकर डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए ये Man-power बहुत काम आ सकता है।

साथियों, हिमाचल की Community और यहां का Potential, आपकी Capital, और यहां की Policy में Clarity, बहुत बड़े परिवर्तन का माध्यम बनेगी। और जब आप यहां के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देंगे, उनके Talent का उपयोग करेंगे, तो ये लाभ कई गुना बढ़ जाएगा।

अंत में आप सभी का एक बार फिर इस समिट में हिस्सा लेने के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं यहां आज मेहमान नहीं हूं मैं भी एक प्रकार से हिमाचली हूं। और इसलिए आप मेरे यहां आए हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब अजमाइए, हिमाचल आपको आर्शीवाद देता रहेगा आप फलेंगे-फूलेंगे, बहुत-बहुत प्रगति करेंगे, हिमाचल भी बढ़ेगा, हिन्दुस्तान भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आप सब को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई और सरकार को भी इस भव्य आयोजन के लिए अनेक-अनेक साधुवाद।

Thank You!

Thank you very much!

PM Modi's address at Rising Himachal Investor's Meet 2019 in Dharamshala...



VRRK/SH

(रिलीज़ आईडी: 1590876) आगंतुक पटल : 456

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Assamese , English , Urdu , Marathi , Bengali , Punjabi , Tamil

प्रधानमंत्री कार्यालय

महालेखाकार एवं उप-महालेखाकार संगोष्ठी में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 21 NOV 2019 9:32PM by PIB Delhi

श्री राजीव महर्षि, दोनों Deputy CAG, देशभर से आए सभी साथी, Friends,

Accountant General में मुझे फिर एक बार आने का मौका मिला है। ज्यादा तो मौका नहीं मिलता है बातचीत करने का लेकिन कुछ समय में भी कुछ अनुभव हो ही जाता है। गांधीजी की 150वीं जन्म-जयंती के वर्ष में ये कार्यक्रम होना, ये भी अपने-आप में सुखद है। और गांधीजी कहते थे कि जिस तरह व्यक्ति अपना पीठ नहीं देख सकता, अपना back नहीं देख सकता, उसी तरह व्यक्ति के लिए अपनी त्रुटियों को देखना भी बड़ा मुश्किल होता है।

लेकिन आप सभी वो दिग्गज हैं जो एक आईना लेकर सरकारी व्यवस्थाओं के सामने खड़े हो जाते हैं- ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, ये process ठीक नहीं है, और आप हिसाब-किताब रखने वालों का हिसाब-किताब करते हैं। लेकिन अभी जो महर्षि जी ने presentation दिखाया, उसमें मुझे खुशी है कि आपने अपना हिसाब-किताब दिखाया, ये अच्छी पहल है।

साथियों, तीन साल पहले जो संगोष्ठी हुई थी, उसमें आप सभी के बीच विस्तार से चर्चा करने का अवसर मुझे मिला था, और उस समय चर्चा के अनेक बिंदुओं पर जैसा मैं देख रहा था, बहुत सी बातों को आपने पकड़ करके उसको लागू करने का काम किया और आगे भी आपकी प्रक्रिया चल रही है। और मुझे याद है कि तब मैंने कहा था, CAG को टुकड़ों में सोचने के बजाय सम्पूर्णता में काम करने की जरूरत है। सिर्फ आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही ये संगठन को सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि वाकई में गुड गवर्नेंस के एक Catalyst के रूप में आगे आना है। CAG को CAG Plus बनाने के सुझाव पर आप गंभीरता से अमल कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और इसके अनेक सुखद परिणाम भी देश को मिले हैं। देश में accountability और probity का माहौल बनाने में इसके कारण एक मदद मिलती है, एक वातावरण बनता है। देश में outcome आधारित time bond तरीके से काम करने की जो व्यवस्था विकसित हो रही है, उसमें CAG की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सब संभव तो हो पा रहा है तो इसके पीछे आप और आपके जो साथी हैं, और विशेषकर जिनको field पर काम करना होता है, field पर जा करके audit करना होता है, कहीं mining चलता है तो उसको वहां जाना पड़ता है, जाकर देखना पड़ता है। और राज्यों में भी जा करके महीनों-महीनों तक AG Office के साथ ही field में डटे रहते हैं, वहां बैठे रहते हैं, एक-एक कागज को छानबीन करते रहते हैं। और कभी-कभी तो परिवार के साथ भी लंबे अर्से की दूरी हो जाती है, और तब जा करके सारी process निकलती है। और ऐसे ही निष्ठावान साथियों के कारण CAG की विश्वसनीयता बनी है और मजबूत हुई है।

साथियों, दशकों से खड़ी की हुई इस व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन लाना अपने-आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि शायद सरकारी व्यवस्थाओं में जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो वो CAG है, 1860 में हुआ? और वो भी 1857 के बाद हुआ था तो उसकी एक हिस्ट्री है। कभी आप लोग गहरे जाआगे तो काफी कुछ मिलेगा उसमें से। आजकल तो reform को एक बड़ा ही fancy word माना जाता है। हर कोई कहता है मैं भी reform करता हूं। कहीं कुछ भी करो, reform में आ जाता है। लेकिन असली reform तब आता है, जब किसी संगठन में पूरी rank और file पूरी ईमानदारी से उसके लिए तैयार होती है, motivate होती है। और ये बात

देश की हर सरकार, हर संस्था, हर संस्थान पर लागू होती है और जिसमें CAG भी है। CAG की जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि आप देश और समाज के आर्थिक आचरण को पवित्र रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इसलिए आपसे उम्मीद भी जरा ज्यादा रहती है।

साथियो, नीति के, अर्थशास्त्र और auditing के प्रेरणा-पुंज चाणक्य कहा करते थे- ज्ञाणं भारं: क्रियां विना- यानी अगर आपके पास knowledge है लेकिन उसको आप सही जगह पर, सही दिशा पर नहीं लगाते हैं तो वो अपने-आप में बोझ बन जाता है वो निरर्थक हो जाता है। और इसलिए आपके पास एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी है। आपको अपने ज्ञान और अनुभव का प्रसार करना है तो साथ-साथ ethics भी मजबूत बनाने हैं- और जिसको चाणक्य ने अपने पूरे नीति शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्व दिया था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के digital world में, बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में Audit और Assurance की भूमिका और उसमें बदलाव बहुत अहम हो चुके हैं।

साथियो, टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर transparency लाने के प्रयास आप सभी बीते पांच वर्षों से निरंतर देख रहे हैं। सरकार का हिसाब-किताब खुला और पारदर्शी रहा है, बल्कि एक dashboard की तरह रहे हैं। जो भी है वो सबके सामने है, जितना भी है वो स्पष्ट दिखता है। टेंडर से लेकर procurement तक एक पारदर्शी प्रक्रिया सरकार ने खड़ी की है। अब अधिकतर टेंडर ऑनलाइन होते हैं, infrastructure से जुड़े प्रोजेक्ट की monitoring भी surveillance scientific तरीके से होती है। JAM यानी जन-धन-आधार मोबाइल- इससे सामान्य मानवी तक सरकारी योजनाओं का लाभ direct पहुंच रहा है। और GEM यानी government e-market place, इससे सरकार अपनी procurement direct करती है। आज सरकारी की 425 से ज्यादा स्कीम का लाभ direct लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। जिसके कारण करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं। विशेषतौर पर जीएसटी जैसे चुनौतीपूर्ण और जटिल सुधार को देश की व्यापारिक संस्कृति का हिस्सा बनाने में तो आपने भी सराहनीय भूमिका निभाई है।

साथियो, आज भारत दुनिया की सबसे अग्रणी digitized economy में से एक है और यहां तेजी से digital infrastructure का निर्माण हो रहा है। Digital व्यवस्था ने नागरिक और सरकार के बीच के interface को, सद्भाव को, विश्वास को तो मजबूत किया ही है, सरकारी प्रक्रियाओं पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। हमारे record maintain करने के तौर-तरीके भी बदलते जाते हैं। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ- पहले जो सरकार को payment होती थी, उसके चालान नागरिकों को, सरकारी दफ्तरों को, ट्रेजरी को, सभी को अलग-अलग रखने पड़ते थे। लेकिन अब physical copy की जरूरत नहीं है बल्कि वो एक App में ही paperless तरीके से स्टोर हो जाता है। इससे जनता को तो सुविधा हुई ही है CAG के audit process में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है।

साथियो, आज जब आज जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें भी आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा असर सरकार की Efficiency पर पड़ेगा, सरकार की Decision Making और Policy Making पर पड़ेगा। आप जो कुछ करेंगे, उसका सीधा असर बिजनेस संस्थानों की Efficiency पर भी पड़ेगा, आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर भारत में निवेश पर पड़ेगा, ease of doing business पर पड़ेगा। आज जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं, उनको सटीक Audit भी चाहिए, ताकि वो अपने Plans का सही Execution कर सकें। वहीं वो ये भी नहीं चाहते कि Audit के Process में बहुत ज्यादा समय लगे। यहीं से आपकी चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए दो काम बहुत जरूरी हैं। एक skill और training से जुड़ा है और दूसरा tools से जुड़ा है। जो नए साथी इस profession से जुड़ रहे हैं, उनको तो updated technology से हमें लैस करना ही है, जो भी काम कर रहे हैं, इनकी skill को upgrade करना भी उतना ही जरूरी है। अब जैसे पूरी दुनिया में जो auditing से जुड़ी संस्थाएं हैं, वे crowd based solution की तरफ बढ़ रही हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी को लेकर जो best global practices हैं, उनको हमें हमारे सिस्टम का हिस्सा तो बनाना ही है, India Pacific tools पर भी हमें काम करना है।

साथियो, हमारा लक्ष्य है कि साल 2022 तक Evidence Based Policy-Making को गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। ये New India की नई पहचान बनाने में भी मदद करेगा। ऐसे में Audit और Assurance Sector के Transformation के लिए भी ये सही दौर है। अब CAG को भी CAG 2.0 की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बताया गया है कि आप इस तरफ तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। ये काम हम तेजी से तभी कर पाएंगे जब कुछ gap को, कुछ कड़ियों को तेजी से जोड़ पाएं। अभी हमारे यहां जो data generate हो रहा है, वो बहुत विशाल है और अनेक एजेंसियों, अनेक विभागों के पास स्टोर है। ये डेटा भी इन एजेंसियों और विभागों ने अपने यूज के लिए collect किया है। लेकिन ये भी सही है कि अक्सर ये डेटा एक-दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता। ये विशाल डेटा लिंक नहीं होता। इसलिए accountability gap भी natural course में आ जाता है। हमें इसे bridge करना है। और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी कुछ कोशिश हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस विषय पर आपस में विचार करेंगे और दूसरी एजेंसियों और विभागों के साथ भी साझा करेंगे। और मुझे याद है पिछली बार मैंने आपके बीच एक ही जिले में road construction का उदाहरण दिया था। ये बताया था कि कैसे एक ही जिले में समान लंबाई की सड़क जब दो अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो कई बार कीमतों में कितना फर्क रहता है। अब अलग-अलग ऑडिट के समय में तो दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन overall picture को देखें तो सही नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण सरकारी विभागों में हैं जहां पर big data analysis सुधार किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जब आप बड़े डेटा बेस को अपने ऑडिट के लिए analyze करते हैं तो आपकी जानकारी Evidence Based Policy-Making में बहुत काम आ सकती है। अगर इसमें CAG इस डेटा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर advice दे सकें, कुछ institutional solution दे सकें, तो मैं समझता हूं इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। और मेरा तो आग्रह ये भी होगा कि आप सिर्फ ऑडिट के लिहाज से ही नहीं एक think tank के नजरिए से भी सोचें।

साथियो, मैंने पिछली बार institutional memory की भी बात की थी। Digital audit और Digital governance, अलग-अलग संस्थाओं में इस institutional memory को भी मजबूत करने का काम कर सकती है। एक और काम आप आसानी से कर सकते हैं, CAG अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ऑडिट करती है, दूसरे देशों को ऑडिट में technical support देती है। आप एक ऐसा institutional mechanism तैयार कर सकते हैं जिसमें International audit करने वाली टीमों अपने अनुभव साझा कर सकें, वहां की best practices को शेयर कर सकें, CAG की ऑडिट रिपोर्ट ज्यादा सार्थक हो। इसके लिए क्या हम audit के topic को विचार-विमर्श करने के लिए चुन सकते हैं क्या? इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आप अनेक प्रकार के audit करके आ रहे हैं। मेरा एक सुझाव है कि आप process audit पर भी गौर करें। अभी तक तो आप सिर्फ यही देखते हैं कि process follow हुआ या नहीं हुआ। लेकिन क्या उस process पर कोई सुधार संभव है, ताकि निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? ये सुझाव आएगा और मैं समझता हूं कि बहुत मददकारक होगा। एक और शिकायत विभागों की तरफ से रहती है कि CAG audit बहुत जल्दी-जल्दी होता है, जिसके कारण जो findings निकलती हैं, वो उतनी काम नहीं आ पाती हैं। क्या ऐसा संभव है कि विभागों के internal audit, उसमें कैसे मजबूती आए, और वो in tune with CAG कैसे हो, ताकि हम समय भी बचा सकें और efficiency बढ़ा सकें। और इससे होगा ये कि routine audit विभाग खुद जब करते हैं तो इन सारी बारीकियों को ध्यान दें ताकि जब CAG वहां जाएं तो उसको जो readymade material मिलेगा, उसमें बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी और हम efficiency बढ़ा सकते हैं, हम speed भी बढ़ा सकते हैं।

साथियो, ये चुनौती उस टेक्नोलॉजी से हमें निपटने की है जो गलत काम करने वालों के पास है। अब CAG सहित तमाम ऑडिटर्स को चाहे वो internal हो, या फिर external हो, नई चुनौतियों से निपटने के लिए innovative तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें ऑडिटर्स की core values को प्रोत्साहित करना होगा, तभी हम occupational fraud पर नकेल कस पाएंगे। बीते कुछ सालों में सरकारी विभागों में fraud से निपटने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। अब CAG को ऐसे technical tools develop करने होंगे ताकि संस्थानों में fraud के लिए कोई गुंजाइश न बचे। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं- मैं पिछले दिनों इसका प्रयोग किया है, क्या CAG इस पर सोच सकता है क्या? मैंने भारत सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंटों से प्रार्थना

की कि आपके पास ऐसी कौन सी problem है, कि जिसके solution में या उन समस्याओं के समाधान में या delivery में आपको दिक्कतें होती हैं? शुरू में तो डिपार्टमेंट के लिए ऐसा स्वीकार करना मुश्किल होता है, तो सबका पहला रिपोर्ट यही आता है, नहीं हमारे यहां कोई तकलीफ नहीं है, सब बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं जरा पीछे लगा रहा, बार-बार पूछता रहा, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स से करीब-करीब 400 issues आए। उनको लगता था कि इसका technological solution हो तो अच्छा हो।

इन 400 issues को मैंने अलग-अलग universities के IT based काम करने वाले students को दिया और पूरे देश में हेकेथॉन चलाया। लाखों नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया। Minimum 36 hours nonstop इन टोलियों ने काम किया। उसमें से निकलते-निकलते-निकलते ऊपर जब करीब 10-12 हजार बच्चे बचे तो मैंने खुद ने उनसे चर्चा की। और आप हैरान हो जाएंगे इन 400 जो issues निकाले थे, अधिकतर का सॉल्यूशन इन 18-20-22 साल के बच्चों ने निकाल करके दिया, technology based solution. और सरकार का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि उसमें से करीब-करीब 80 पर्सेंट उन्होंने already अपनी व्यवस्था में incorporate कर दिया, लागू कर दिया। क्या CAG आज जो चुनौतियां हैं, जैसे अब आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि ये हॉस्पिटल का ऑडिट करना इन्हें कितना बड़ा टेक्नीकल काम है, कैसे करना है। अब आप तो उस फील्ड के हैं नहीं। कोई एक डॉक्टर मिल जाए, वो आपको कहे तो आप उस दिशा में जा करके देख लेंगे। क्या हम इस प्रकार की चीजों के लिए identify करके इतने-इतने issues हैं, technical solutions निकाले जा सकते हैं।

तो आप अगर इस प्रकार से issues इन नौजवानों को दें और मैं एचआरडी मिनिस्ट्री को कह सकता हूं कि भी इसके साथ coordinate करें। और इस प्रकार के हेकेथॉन हों जो CAG के लिए ऐसे tool बनाएं, CAG के लिए इस प्रकार के सॉल्यूशंस ले करके आए। आपके कुछ लोगों को उनके साथ विचार-विमर्श करने का मौका मिले तो मैं समझता हूं एक अच्छा mechanism और ये yearly किया जा सकता है। ये हेकेथॉन, इससे ये भी लाभ होगा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था की सबसे वृद्ध, अनुभवी ये institution कैसे-कैसे काम कर रही है और कितनी चुनौतियों को ले करके चलती है। मैं समझता हूं कि इस काम की ओर सोचा जा सकता है और देखना चाहिए। और ऐसे प्रयासों से देश के सामान्य मानवी की परेशानी कम होगी और देश की तमाम संस्थाओं पर उसका भरोसा भी मजबूत होगा। At the same time Government mechanism जो है, उसका और आपका भी- इन दोनों में तारतम्य बनेगा।

मुझे विश्वास है कि CAG देश की तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और न्यू इंडिया को clean India, Clean India- वो वाला नहीं जो मैं करता हूं, आप वाला दूसरा है- बनाने में अपनी भूमिका को सशक्त करेगी। और मेरा आपसे आग्रह है- एक तो होता है हम ऑडिट करें। लेकिन क्या ऑडिट किसी को कटघरे में खड़ा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हम वहीं पर रुकने के लिए हैं क्या? जी नहीं, हम कहीं पर भी हों, किसी भी अम्ब्रेला के नीचे काम करते हों, लेकिन ultimately हम सब देश के लिए काम करते हैं, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। और इसलिए हम ये जो मेहनत करते हैं, क्या वो good governance के लिए काम आ सकती है क्या? Efficiency के लिए काम आ सकती है क्या? और ये किया जा सकता है- जैसे हर बार जरूरी नहीं है कि जो है उसमें से हम कमियां खोजें, हर बार जरूरी नहीं है। लेकिन अगर साल के प्रारंभ में ही आप एक दस डिपार्टमेंट पकड़ लें। दस डिपार्टमेंट के संबंध में brain storming हो, डिपार्टमेंट के साथ, आपके लोगों के साथ, जिस-किस में महारत है, grass root level पर भी कोई काम करने वाला हो, वो भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाला हो, स्टेट लेवल पर करने वाला हो, नेशनल लेवल पर हो।

Brain storming करके मान लीजिए एक direct आप 100 point निकालते हैं, और उनको कहा जाए कि देखिए भाई हम एक साल के बाद ऑडिट के लिए आएंगे। ये हम सबने मिलकर जो 100 point निकाले हैं, आप अपने काम का इस 100 point के तराजू पर जरा तौलिए। आप जो चीजें रिकॉर्ड रखेंगे, इन 100 पहलुओं को उसमें जरूर ध्यान रखिए।

इसका मतलब ये हुआ कि जो audit mind है वो पहले से उसको इंगित करेगा कि देखिए आपको गलती न हो, इसके के लिए मैं आपको प्रोफार्मा देता हूं। आप देखिए, इससे फर्क ये पड़ेगा efficiency बढ़ेगी, governance के पहलू में नई बातें उजागर होंगी, जो सरकार की अपने-आप में एक strength बन जाएगी। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम ऐसे भी कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? दूसरा आपने देखा होगा, ultimately आपने देखा होगा, हम बजट में, हाउस में हम outcome report भी रखते हैं, जो पहले हमारे यहां नहीं था। क्योंकि output की चर्चा तो बड़ी सरल होती है, कि दस रुपया था, दस रुपया दे दिया। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सारी बातें- वो आपके क्षेत्र में चला जाता है। और वो outcome शुरू होता है। और इसलिए हाऊस के अंदर इन दिनों outcome की व्यवस्था हमने develop की है और ये institutionalized की है।

लेकिन कभी-कभी process बढ़िया, प्रॉडक्ट बढ़िया, outcome क्या? Outcome कहां कम होता है, जहां पर चोरी होती है वहां outcome कम होता है बात अलग है, ज्यादातर bad governance उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर गर्वनेंस सही है तो natural course में outcome और efficiency नजर आती है। और इसलिए हम अपनी बातों को good governance का भी एक हिस्सा बना सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा क्या Target था, क्या Achieve किया गया, और इसको लेकर आपका दृष्टिकोण बारीक होते हुए भी मैं जरूर चाहूंगा कि हम एडवांस में अपने-अपने संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं- हम प्रयास करें।

मैं फिर एक बार- आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। आप सबको देश की एक उत्तम सेवा करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे। क्या CAG 2022 आजादी के 75 साल as an institution हमारे target क्या होंगे? हम इस institution को और अधिक friendly कैसे बनाएंगे? Productive कैसे बनाएंगे? Good governance में contributor कैसे बनाएंगे? हमारे इस अनुभव का उपयोग बुराइयों दूढ़ने की जिसकी ताकत है, उसकी बुराइयों को रोकने की भी ताकत होती है। जिसकी बुराइयों को रोकने की भी ताकत होती है, जिसको बुराइयां होने से बचाने की भी ताकत होती है, क्या हम इन्हीं सभी पहलूओं के साथ जुड़ करके इस सारी इतनी बड़ी institution का हम और अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं? और मैं मानता हूं कि संभव है।

आपको लगेगा कि फाइलें देख-देख करके तंग आ जाते हैं और ये प्रधानमंत्री चार काम नए दे करके जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर आपका जो ये बोझ है, वो अपने-आप कम हो जाएगा और आपको भी संतोष होगा कि आपने जो और contribute किया है, वो institutionalized हुआ है जिस तरह देश के नक्शे को जो एक सोच है उसको बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और ये हो सकता है।

इसी अपेक्षाओं के साथ मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

PM's speech at Conclave of Accountants General & Deputy Accountants Ge...



वी.रवि रामा कृष्णा/शाहबाज़ हसीबी/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा-4336

(रिलीज़ आईडी: 1593009) आगंतुक पटल : 635

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali

प्रधानमंत्री कार्यालय

ASSOCHAM के सौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 20 DEC 2019 1:26PM by PIB Delhi

ASSOCHAM के प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका जी, सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद जी, ASSOCHAM के लाखों सदस्यगण, भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों !!!

ASSOCHAM ने आज एक बहुत अहम पड़ाव पार किया है। सौ वर्ष का अनुभव व्यक्ति हो या संस्था बहुत बड़ी पूंजी होता है। मैं ASSOCHAM के सभी सदस्यों को, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मुझे बताया गया है कि करीब-करीब सौ लोकेशन पर ये आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को, उद्यमियों को और विशेषकर MSME सेक्टर से जुड़े लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ।

Friends,

2019 में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 2020 का नया वर्ष और नया दशक, आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

साथियों,

आपने अपने सेन्टेनरी सेलिब्रेशन की जो थीम रखी है, वो देश के, देशवासियों के लक्ष्यों और सपनों के साथ जुड़ी है। और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई हो, ऐसा नहीं है। बीते पाँच वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था Disaster की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि अर्थव्यवस्था में एक Discipline लाने का प्रयास किया है।

भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले, तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं, चौतरफा फैसले लिए हैं, उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। और इसलिए आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार बना है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को Formalization और Modernization के दो महत्वपूर्ण Pillars पर खड़ा कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए तमाम उपायों से लेकर GST तक, आधार Linked Payment से लेकर DBT तक,

हमने अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को Formal व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए Modernize और Speed-Up करने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं।

अब कई हफ्तों के बदले कुछ घंटों में Company Registration हो जाना, Trading Across Borders में Automation के जरिए समय कम करना, Infrastructure की बेहतर Linkage के जरिए Port और Airport पर Turn Around Time का कम होना, ये सब आधुनिक होती अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं।

साथियों,

आज देश में वो सरकार है जो उद्योग जगत की सुनती है, उनकी आवश्यकताओं को समझती है और उनके सुझावों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करती है। क्या उद्योग जगत नहीं चाहता था कि देश में टैक्स का जाल कम हो, हर राज्य में अलग-अलग दरों की परेशानी से उसे मुक्ति मिले? हमारी सरकार ने दिन रात एक करके आपकी इस मांग को पूरा किया, हम GST लेकर आए। इतना ही नहीं, व्यापारी जगत से जो-जो Feed Back मिला, हम GST में सुधार भी करते रहे।

साथियों,

बरसों से भारत का उद्योग जगत Business को आसान बनाने की मांग कर रहा था, प्रक्रियाओं को Transparent और Simple करने की मांग कर रहा था। आपकी इस मांग पर भी हमारी ही सरकार ने काम किया। आज भारत दुनिया के उन टॉप टेन देशों में शामिल है जिसने Ease of Doing Business की रैंकिंग में पिछले तीन वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है। 190 देशों की रैंकिंग में हम 142 से अब 63वीं रैंक पर आ गए हैं। क्या ये आसान बात है?

Ease of Doing Business कहने में चार शब्द लगते हैं लेकिन इसकी रैंकिंग में बदलाव तब होता है जब दिन-रात मेहनत की जाती है, जमीनी स्तर पर जाकर नीतियों में, नियमों में बदलाव होता है।

चाहे बिजली कनेक्शन देने की बात हो, कंस्ट्रक्शन परमिट की बात हो, Export-Import पर Clearance की बात हो, सैकड़ों प्रक्रियाओं के सरल बनाने के बाद, अनेकों रुकावटों को पूरी तरह हटाने के बाद इस तरह की रैंकिंग में सुधार होता है। हम इसे आगे भी लगातार सुधारने के लिए काम कर रहे हैं।

Friends,

आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि Companies Act में सैकड़ों ऐसे प्रावधान थे, जिसमें छोटी-छोटी गलतियों के लिए Criminal Action की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने इसमें से अनेक प्रावधानों को अब De-Criminalise कर दिया है। कई और प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की प्रक्रिया अभी जारी है।

इसी तरह हमारी सरकार Inverted Duty खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पिछले वर्षों में आए बजट में इसका ध्यान रखा गया है। इसकी वजह से भारत में Manufacturing पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है।

साथियों,

इस साल अक्टूबर से देश के टैक्स सिस्टम से जुड़ी एक और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। हमने उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाया है जहां Taxpayer और Income Tax Department के बीच Human Interface नहीं होगा। टैक्स सिस्टम में Transparency, Efficiency और Accountability लाने के लिए हम Faceless Tax Administration की ओर बढ़ रहे हैं।

Friends,

Corporate Tax कम करने, उसका Process Simplify करने को लेकर भी बरसों से देश में तमाम चर्चाएं होती थीं। इसे लेकर भी ठोस कदम किसने उठाया? हमारी ही सरकार ने। देश में जितना CorporateTax आज है, उतना कम कभी नहीं रहा है। मतलब उद्योग जगत से सबसे कम CorporateTax लेने वाली सरकार अगर कोई है, तो वो हमारी सरकार है।

साथियों,

Labor Reforms की बातें भी बहुत वर्षों से देश में चलती रही हैं। कुछ लोग ये भी मानते थे कि इस क्षेत्र में कुछ न करना ही लेबर वर्ग के हित में है। यानि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, जैसे चलता रहा है, वैसे ही आगे भी चलेगा। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं मानती।

हम मानते हैं कि जो Labour Force है उसकी भी हर तरह से देखभाल होनी चाहिए। उनका जीवन आसान बने, उनको प्रोविडेंट फंड समय से मिले, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इन सारे क्षेत्रों में सरकार ने काम किया है।

इसलिए लेबर यूनियनों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, हमने लेबर कानून में बहुत से ऐसे बदलाव भी किए हैं जो समय की मांग हैं। लेकिन Friends, अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए, उद्योग जगत के हित में उठाए जा रहे ऐसे हर फैसले पर सवाल उठाना ही कुछ लोगों ने अपना दायित्व समझ लिया है।

जब 2014 से पहले के बरसों में अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उस समय अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग किस तरह तमाशा देखते रहे, ये देश को कभी नहीं भूलना चाहिए।

हमें विरासत में किस तरह की अर्थव्यवस्था मिली थी, तब अखबारों में किस तरह की बातें होती थीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख कहाँ थी, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन उस दौरान जो स्थितियाँ थीं, उनके प्रभावों को कम करने के लिए जो स्थाई उपाय हमने किए, वो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा आधार बने हैं।

Friends,

आप ये भी भली-भाँति जानते हैं कि 2014 से पहले देश का बैंकिंग सिस्टम किस तरह के संकट में था। तब हालत ये थी कि बैंकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब-करीब 6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। इसमें सरकार द्वारा पहले इंद्रधनुष प्लान के तहत 70 हजार करोड़ रुपए और फिर recap के माध्यम से 2 लाख 36 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।

साथियों,

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अब 13 बैंक मुनाफे में वापस आ चुके हैं। 6 बैंक PCA से भी बाहर निकल चुके हैं। हमने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया है। बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में, किसी तरह की दखलअंदाजी को समाप्त कर दिया है।

सरकार के दखल के बिना काबिल लोगों की पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो, इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। इसमें आरबीआई और बाहरी एक्सपर्ट्स रखकर उन्हें पूरी ऑटोनॉमी दी गई है। अब आप बैंकों में सीनियर पदों पर नियुक्ति होने पर कोई murmuring नहीं सुनते होंगे !!!

Friends,

हमारी सरकार मानती है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कई बार हमें कंपनियों की असफलता को, उनके Failures को भी स्वीकार करना पड़ता है। सारी असफलताएं, किसी आर्थिक अपराध की वजह से हों, ऐसा भी नहीं हैं। इसलिए, कंपनियों को, कंपनियां चलाने वालों को एक बेहतर Exit Route मिले, इस ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है।

IBC-Insolvency and Bankruptcy Code आज ऐसी अनेक कंपनियों का मददगार बन रहा है, जो किसी वजह से Failures का सामना कर रही हैं।

ये सरकार की तरफ उद्योग जगत की एक तरह से Hand Holding का प्रयास है ताकि ऐसी कंपनियां अपने अनुभवों से सीख सकें, भविष्य में कुछ और अच्छा कर सकें।

साथियों,

ये जितने भी फैसले मैंने बताए हैं, वो उद्योग जगत को, उसकी पूंजी को Safe-Guard करने में बहुत मदद करने वाले हैं।

मैं आज ASSOCHAM के इस मंच से, देश की बैंकिंग से जुड़े लोगों को, कॉर्पोरेट जगत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जो पुरानी कमजोरियां थीं, उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसलिए खुलकर फैसले लें, खुलकर निवेश करें, खुलकर खर्च करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सही निर्णयों पर और Genuine Commercial Decision पर कोई अनुचित कार्रवाई नहीं होगी।

Friends,

आज हम ये कह सकते हैं कि देश की बैंकिंग प्रणाली की नींव अब इतनी पारदर्शी और मजबूत हुई है कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को Power दे सकती है, ऊर्जा दे सकती है। आज भी हम दुनियाके 10 सर्वश्रेष्ठ FDI destinations में से एक हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में FDI आने की गति बढ़ी है।

मेरा मानना है कि एफडीआई के दो अर्थ हैं। अवसर के हिसाब से मैं उन दोनों का उपयोग करता हूं। एक अर्थ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है जिसे आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, और अन्य मेरे लिए "पहले विकसित भारत" है। पिछले 20 वर्ष में जितनी FDI देश में आई उसकी लगभग 50 प्रतिशत पिछले 5 वर्षों में आई है। हमने पिछले सालों में अपनी global competitiveness में भी व्यापक सुधार किया है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा Start-Up Ecosystem हमारे देश में है। देश में Innovation और Enterprise का एक नया वातावरण बना है। आज दुनिया के ज्यादातर निवेशक भारत की तरफ पूरे विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं। भारत की क्षमता को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व भरोसा उत्पन्न हुआ है।

साथियों,

इसी Positivity के आधार पर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश, इसे ताकत देगा। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए होने वाला साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश इसे नई शक्ति देगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण हो या हर देशवासी तक Affordable Healthcare पहुंचाने का संकल्प, किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास हों या देश के लाखों MSMEs, करोड़ों सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आसान फंडिंग, ऐसे अनेक प्रयास, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए नई ऊर्जा देंगे, नया विश्वास देंगे।

साथियों,

भारत की अर्थव्यवस्था को करीब-करीब दोगुना करने के लिए हमारे प्रयास सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, इसके लिए हम राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। Manufacturing और Export को बढ़ाने के लिए, Make In India को विस्तार देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नॉलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हमारी प्राथमिकता में है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

साथियों,

इस सारी बातों के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर आज जो चर्चाएं हो रही हैं, मैं उससे भी भली-भांति परिचित हूं। लेकिन उन चर्चाओं के बीच हमें ये भी याद करना होगा कि पहले की सरकार के समय एक क्वार्टर में GDP की विकास दर 3.5 Percent तक पहुंच गई थी।

याद करिए, उस दौर में CPI headline inflation कहां तक पहुंची? 9.4 percent तक। CPI core inflation कहां थी? 7.3 percent...!!! WPI inflation कितने तक पहुंची थी? 5.2 percent तक। Fiscal Deficit कहां तक गया था? GDP के 5.6 percent तक। उस समय GDP के अनेक क्वार्टर्स ऐसे गए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय कुछ लोग क्यों चुप रहे।

Friends,

देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार-चढ़ाव पहले भी आए हैं। लेकिन देश में वो सामर्थ्य है कि वो हर बार ऐसी स्थिति से बाहर निकला है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला है। इसलिए अभी की स्थिति से भी भारत अवश्य बाहर निकलेगा।

साथियों,

भविष्य के लिए हमारे इरादे भी साफ हैं और हौसले भी बुलंद हैं। इस सरकार की पहचान ही यही है कि जो कहती है वो करती है। 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य भी इसलिए संभव है क्योंकि ऐसी अनेक बातें, जो पहले भी असंभव लगती थीं, उन्हें देश ने संभव करके दिखाया है। 60 महीने में 60 करोड़ आबादी को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना असंभव दिखता था, आज ये संभव हुआ है। 3 साल से भी कम समय में 8 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना, 10 लाख से अधिक गैस डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर खड़े करना, असंभव लगता था लेकिन संभव हुआ है।

हर परिवार को इतने कम समय में बैंकिंग से जोड़ना पहले असंभव लगता था, लेकिन संभव हुआ है। देश की एक बड़ी आबादी तक डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाना भी पहले असंभव दिखता था। आज देश में हर रोज करोड़ों डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। BHIM app और Rupay card भी इस देश में इतने प्रचलित हो जाएंगे, ये किसने सोचा था? लेकिन आज ये संभव हुआ है। हर बेघर को अपना पक्का घर देना असंभव लगता था, लेकिन ये संभव हो रहा है। अब इसमें मैं बीते 6 महीने के उदाहरण और देने लगूंगा, तो आपका लंच ब्रेक तो गया समझिए।

साथियों,

संकल्प से सिद्धि के, इसी सकारात्मक और पारदर्शी माहौल में, आपके लिए भी अवसरों का विस्तार हो रहा है।

आपका हौसला पहले से बेहतर हो, कृषि से लेकर कंपनियों तक मैं Production पहले से बेहतर हो, और आपके द्वारा Wealth Creation और Job Creation भी पहले से बेहतर हो, इसके लिए सरकार हर तरह से भारत के उद्योग जगत के साथ खड़ी है। मैं इस मंच के माध्यम से, देश के उद्यमी को यही कहूंगा कि आप आगे बढ़िए, आप समर्थ हैं, सक्षम हैं। पूरी दुनिया का बाजार हमारे सामने है। पूरी दुनिया को टक्कर देने का साहस हमारे भीतर है। आपका संकल्प, आपका सामर्थ्य 5 ट्रिलियन डॉलर के भारत के सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।

आपकी समृद्ध परंपरा, 21वीं सदी के न्यू इंडिया को भी विस्तार देने वाली है, मजबूत करने वाली है। आप सभी अपने प्रयासों में सफल हों, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

धन्यवाद !!!

PM Modi addresses centenary celebrations of ASSOCHAM



वीआरआरके/वीजे

(रिलीज़ आईडी: 1597034) आगंतुक पटल : 571

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Assamese , Punjabi , English , Urdu , Marathi , Tamil